

शॉपिंग ट्रेड में युवाओं और बुजुर्गों को एक साथ लाया कोविड

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सामाजिक दूरियां बढ़ीं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हुए। इसके बावजूद कम से कम एक क्षेत्र ऐसा रहा, जहां पर युवाओं और बुजुर्गों के बीच दूरी कम हुई है। कोविड काल में विभिन्न शॉपिंग मॉल में अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की खरीदने के मामले में भारतीय युवा और बुजुर्ग एक ही ढर्रे पर चले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की ओर से

लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ शोधपत्र

अंतरराष्ट्रीय जर्नल में छपे शोधपत्र में यह दावा किया गया है। यह शोधपत्र समाजशास्त्र विभाग के शिक्षक डॉ. पवन मिश्रा और उनकी शोधार्थी आयुषी वर्मा ने प्रकाशित किया है। डॉ. पवन मिश्रा ने बताया कि यह शोधपत्र मलेशिया की अंतरराष्ट्रीय जर्नल साउथ एशियन जर्नल फॉर सोशल साइंस में छपा है। डॉ. मिश्रा के अनुसार भारत और विदेश में उम्र के आधार पर होने वाली खरीदारी में

इम्युनिटी बूस्टर पर सबसे ज्यादा खर्च

शोधपत्र के अनुसार सभी आयु वर्ग के ग्राहकों ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा खर्च इम्युनिटी बूस्टर करने वाले उत्पादों पर खर्च किए हैं। ये च्यवनप्राश, आंवल, नीम के तेल जैसे विभिन्न उत्पाद थे। अभी तक इनकी खरीद केवल कुछ विशेष वर्ग द्वारा ही होती थी, लेकिन कोरोना के समय यह अंतर मिट गया।

काफी अंतर है। विदेशों की बात करें तो वहां पर अनिवार्य वस्तुओं के बाद की वस्तुओं की खरीद एक जैसी होती है। उम्र के आधार पर उनमें कोई अंतर नहीं होता है। भारत में ऐसा नहीं है। यहां पर बुजुर्ग और युवाओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं में काफी अंतर होता है। इस अंतर को समझने

के लिए विदेश और भारत में प्रकाशित 70 शोधपत्रों पर अध्ययन किया गया। इनके अध्ययन में एक बात निकलकर सामने आई कि भारत में अनिवार्य वस्तुओं के बाद कोविड काल में युवा और बुजुर्गों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं काफी हद तक एक समान रही हैं।

आपूर्ति और रुपये की कमी ने भी डाला अंतर

डॉ. पवन मिश्रा के अनुसार कोविड के समय युवा और बुजुर्गों की क्रय मानसिकता एक जैसी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा वस्तुओं की आपूर्ति तथा धन की कमी की वजह से क्रय शक्ति न हो पाना भी है। आमतौर पर शॉपिंग मॉल में काफी ऐसी वस्तुओं की खरीद होती है, जिनकी लिस्ट घर से बनाकर नहीं ले जाई जाती है। कोविड के समय विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति में कमी आई है। इसके साथ ही रुपये की कमी भी इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है।

ग्रामीण और आदिवासी बाजार शहरियों के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित

समाजशास्त्र विभाग से प्रकाशित एक अन्य शोधपत्र ने भी दिलचस्प निष्कर्ष दिए हैं। इसके अनुसार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में लगने वाले बाजार शहर में लगने वाले बाजारों की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित होते हैं। यह अध्ययन उत्कृष्ट जर्नल में छपने वाले 50 शोधपत्रों के अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इसको अध्ययन को भी साउथ एशियन जर्नल फॉर सोशल साइंस ने मान्यता देते हुए शोधपत्र के रूप में प्रकाशित किया है।

JAGRAN CITY PAGE IV

शोधार्थियों की उपस्थिति 70 प्रतिशत अनिवार्य

जासं, लखनऊ: लखनऊ विवि के पीएचडी अध्यादेश-2020 में फैकल्टी से लेकर छात्रों के लिए कई नए बदलाव लागू किए गए हैं। फुल टाइम पीएचडी के शोध छात्रों की अंतिम छह महीने में 70 फीसद उपस्थिति अनिवार्य होगी। वहीं, नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर एक साल बाद भी शोध छात्रों को अपने यहां पंजीकृत कर सकेंगे।

अभी तक यह समय सीमा तीन साल की थी। विश्वविद्यालय प्रशासन पीएचडी कोर्स वर्क को भी रिवाइज्ड करके इसमें रिसर्च एथिक्स सहित नई चीजें शामिल करेगा। यह बदलाव आगामी पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से दखिला लेने वाले शोधार्थियों के लिए लागू होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी के नए अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी थी। अब शोधार्थी अपनी विभागीय शोध समिति से अनुमति लेकर दो सेमेस्टर (एक साथ नहीं) के लिए डाटा कलेक्शन व नमूनों की जांच आदि के लिए बाहर भी जा सकेंगे।

VOICE OF LUCKNOW PAGE 3

एनआईआरएफ के लिए लविवि ने किया आवेदन

देश के शीर्ष संस्थानों का विभिन्न कैटेगरी के अनुसार होता है मूल्यांकन

वरिष्ठ संवाददाता (VOL)

लखनऊ। पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक की दौड़ में शामिल हो गई है। हालांकि, केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छह साल पहले शुरू हुई लेकिन लविवि ने दावेदारी करने में पहली बार हिस्सा दिखाया है। ऐसे में देश के टॉप इंजीनियरिंग, लॉ यूनिवर्सिटी व कॉलेज और अन्य से लविवि का सीधा मुकाबला है।

राजधानी से इससे पूर्व डॉ. राम मनोहर

- लविवि में रैंकिंग के लिए जनता की राय भी अहम
- छह वर्ष पूर्व शैक्षिक गुणवत्ता के लिए गठित हुई थी एनआईआरएफ

लोहिया राष्ट्रीय विधि विवि, केजीएमयू, एकेटीयू और बीबीएयू दौड़ में रहे हैं। लविवि के अधिकारियों के अनुसार नौ में से पांच श्रेणियों में आवेदन किया है। एमएचआरडी को भेजे गए प्रस्ताव में विवि के 2020-21 सत्र में छात्रों के परिणाम, यहां के प्रकाशन, अवार्ड हुई डिग्रियां, पेटेंट फाइल, प्रोजेक्ट्स, शोध, शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की योग्यता आदि के बारे में जानकारी दी गई है। अब मंत्रालय में गठित टीम प्रपोजल की

जांच करेगी और कमियां होने पर संशोधन के लिए भेजेगी। उम्मीद जतायी कि लविवि को एनआईआरएफ में अच्छी रैंक मिलेगी।

रैंकिंग के आधार पर मिलता फंड: देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनआईआरएफ का गठन किया गया



है। शिक्षा मंत्रालय हर साल इसे जारी करता है। केन्द्र सरकार नैक रैंकिंग और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर ही संस्थानों को फंड मुहैया कराती है। वहीं, फ्रेमवर्क संसाधनों, अनुसंधान और हितधारक की धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्यों

के लिए कई मापदंडों को देखा जाता है। इन्हें पांच समूहों में बांटा गया है।

एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए यह भी मायने रखता है कि संस्थान के बारे में पब्लिक की क्या राय है? जनता की राय के 25 अंक जुड़ते हैं। इसके लिए विवि यह प्रस्ताव अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है। वहीं, मंत्रालय अखबारों के जरिये विज्ञापन जारी करता है और जनता की राय मांगता है। संबंधित संस्थान के बारे में जो राय मिलती उसके भी अंक रैंकिंग में जुड़ते हैं। जानकारी के अनुसार इस महीने के आखिरी में एनआईआरएफ की रैंकिंग जारी होगी। एनआईआरएफ 29 सितंबर 2015 को शुरू किया गया था। देश में पहली बार चार अप्रैल 2016 को एमएचआरडी ने रैंक सूची जारी की थी। इसमें विवि व कॉलेजों के अलावा इंजीनियरिंग, फार्मसी व प्रबंधन संस्थान और वास्तुकला संस्थानों जैसे ऑपरेशन के अपने क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न तरह के संस्थानों के लिए अलग रैंकिंग रखी है।

RASHTRIYA SAHARA PAGE 2

समापन कार्यक्रम में कुलपति ने बांटे सर्टिफिकेट



लखनऊ। वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय मिशन शक्ति कार्यक्रम के समापन पर कुलपति प्रो. आलोक राय ने विषय 'यौन अपराध : किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों को समर्थन' पर अपने विचार प्रकट किए, साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिभागी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल द्वारा पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में रंगोली, भाषण, कविता, स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता में 80 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

मिशन शक्ति की कोऑर्डिनेटर शीला मिश्रा ने वच्चों की जागरूकता के लिए समाज में स्त्रियों के मूल्य एवं समानता पर जोर दिया। वाणिज्य विभाग की शिक्षिका डा. सुनीता श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संचालन किया।

NBT PAGE 6

एलयू: स्पोर्ट्स सामानों की खरीद पर फैसला आज

■ एनबीटी, लखनऊ: एलयू के न्यू कैंपस में 12 खेलों के अलावा अल्ट्रा मॉर्डन जिम के लिए उपकरणों की खरीद को लेकर मंगलवार को बैठक होगी। विवि की कल्चरल एवं स्पोर्ट्स कमिटी ने कुलपति को जरूरी सामान खरीदने के लिए पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार उपकरणों की सूची तैयार हो चुकी है। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक में मुहर लगेगी। कल्चरल एवं स्पोर्ट्स कमिटी के अध्यक्ष उग्रसेन वर्मा ने बताया कि न्यू कैंपस में जिम के लिए पर्याप्त जगह है। ऐसे में लंबे समय से उपकरणों की मांग चल रही थी।

HINDUSTAN PAGE 8

कुलपति ने कुरीतियों को रोकने पर जोर दिया

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय मिशन शक्ति कार्यक्रम में दूसरे दिन कुलपति प्रोफेसर आलोक राय भी शामिल हुए। यौन अपराध के सम्बंध में आयोजित कार्यक्रम में समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल दिया गया। कार्यक्रम में रंगोली, भाषण, कविता, स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता

में तमाम प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार ने दिया। कुलपति ने विद्यार्थियों को समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए एवं उन्हें जागरूक करने पर विशेष जोर दिया। मिशन शक्ति की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शीला मिश्रा ने अपने संबोधन में वच्चों की जागरूकता के लिए समाज में स्त्रियों के मूल्य एवं समानता पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर, शोधार्थी और छात्र शामिल हुए।